आउटकम/परफॉरमेन्स बजट 2024–25

विभाग– सूचना प्रौद्योगिकी

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउटले/बजट		01.04.2023 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक स्थिति)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड आउटपुट) वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड आउटकम) वर्ष 2024–25	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1.	राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढ़ीकरण	राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन तथा सूचना प्रौद्योगिकी पहल से राज्य में आई0टी0 का सुदृढ़ीकरण।	2190.00	0.01	• सूचना प्रौद्योगिकी भवन का अनुरक्षण एवं संचालन।	• आई.टी. पार्क में आवंटित अतिरिक्त भूमि पर नये भवन निर्माण कार्य गतिमान।	• भवन निर्माण कार्य पूर्ण एवं संचालन।	राज्य में समस्त सूचना प्रौद्योगिकी तथा ई–गवर्नेन्स परियोजना का संचालन कर ई–गवर्नेन्स/ गुड गवर्नेन्स तथा नागरिकों को इलेक्ट्रोनिक माध्यम से सेवायें प्रदान करना।	एक वर्ष
					• ITDA ढांचे के अन्तर्गत अनुबन्ध / आउटसोर्स पर तैनात कर्मियों का वेतन/ परिलब्धियां 18	• संशोधित ढांचे के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति/ अनुबन्ध / आउटसोर्स पर तैनात कर्मियों का वेतन/ परिलब्धियां 21	• संशोधित ढांचे के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति/ अनुबन्ध / आउटसोर्स पर तैनात कर्मियों का वेतन/ परिलब्धियां 42		
					• मुख्यमंत्री हैल्प लाईन 1905 का संचालन	• मुख्यमंत्री हैल्प लाईन 1905 का संचालन	• मुख्यमंत्री हैल्प लाईन 1905 का संचालन		
					• ड्रोन रिसर्च सेंटर का संचालन एवं ड्रोन सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम	• ड्रोन रिसर्च सेंटर का संचालन एवं ड्रोन सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम	• ड्रोन रिसर्च सेंटर का संचालन तथा ड्रोन पायलट के प्रशिक्षण हेतु ड्रोन नीति के अनतर्गत 02 ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना		

					• अपणि सरकार पोर्टल पर अपडेटेड कुल 569 सेवायें लाईव, जिनमें से 394 विकसित / एकीकृत की गयी एवं 175 रि–डायरेक्ट की गयी। • पी0एम0 गतिशक्ति (उन्नति) पोर्टल का क्रियान्वयन, 10 मॉड्यूल के माध्यम से परियोजनाओं की मोनिटरिंग, 767 प्रोजेक्ट्स पंजीकृत।	• अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से 800 सेवायें लाईव। • DBT के अन्तर्गत 10 विभागों की 53 स्कीम लाईव। • पी0एम0 गतिशक्ति (उन्नति) पोर्टल का क्रियान्वयन, 20 मॉड्यूल के माध्यम से परियोजनाओं की मोनिटरिंग, 1000 प्रोजेक्ट्स पंजीकृत।	• सेवाओं के डेवलपमेंट एवं सेवाओं के अनुरक्षण एवं संचालन के लिए के लिए इनहाउस टीम के माध्यम से 1000 सेवायें लाईव एवं DBT के अन्तर्गत 178 स्कीम लाईव। • पी0एम0 गतिशक्ति (उन्नति) पोर्टल का क्रियान्वयन, समस्त 20 मॉड्यूल के माध्यम से परियोजनाओं की मोनिटरिंग एवं समस्त सम्बन्धित प्रोजेक्ट्स पंजीकृत।		
					• स्टेट डाटा सेंटर का संचालन। 85 विभागों की 133 एप्लीकेशन्स होस्टेड थी।	• स्टेट डाटा सेंटर का संचालन अभी तक 93 विभागों की कुल 152 एप्लीकेशन्स होस्टेड।	• समस्त विभागों को सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित। • SDC विस्तारीकरण • Disaster Recovery का प्रावधान।		
					• ई–ऑफिस का कियान्वयन सचिवालय, विभिन्न राजकीय विभागों तथा संस्थाओं के 239 कार्यालयों में क्रियान्वयन।	• ई–ऑफिस का 165 विभागों के 450 कार्यालयों में क्रियान्वयन।	• राज्य के समस्त विभागों तथा कार्यालयों में ई–ऑफिस का क्रियान्वयन।		
					–	• Emerging Technology हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेल का गठन।	• Emerging Technology Cell के माध्यम से ई–गवर्नेन्स के अन्तर्गत आधुनिक तकनीक का उपयोग।		

2.	क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क (स्वान) का क्रियान्वयन तथा विभागों में होरिजोन्टल कनेक्टिविटी	योजना में स्वतंत्र सरकारी नेटवर्क स्थापित कर इसके माध्यम से G2C एवं G2G सेवायें उपलब्ध कराये जाना।	1800.00	-	• ब्लोक/तहसील स्तर तक स्थापित 133 प्वाइंट ऑफ प्रजेन्स के माध्यम से स्वान नेटवर्क का क्रियान्वयन एवं संचालन • BSNL के अतिरिक्त एयरटेल को वैकल्पिक इण्टरनेट सर्विस प्रोवाईडर का चयन • हॉरिजॉन्टल कार्यालय स्वान से संयोजित–1960 • स्वान नेटवर्क का समस्त जनपदों में अपग्रेडेशन पूर्ण	• 139 प्वाइंट ऑफ प्रजेन्स के माध्यम से स्वान नेटवर्क का क्रियान्वयन एवं संचालन • बी.एस.एन.एल. एवं एयरटेल के माध्यम से समस्त स्वान केन्द्रों में कनेक्टिविटी संचालित • हॉरिजॉन्टल कार्यालय स्वान से संयोजित–2050	• दो इण्टरनेट सर्विस प्रोवाईडर के माध्यम से कनेक्टिविटी। • फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेस के अन्तर्गत 217 तकनीकी मानव संसाधन के माध्यम से स्वान नेटवर्क के संचालन एवं नेटवर्क का अनुरक्षण। • समस्त विभागों तथा कार्यालयों को हॉरिजॉन्टल कनेक्टिविटी प्रदान करना।	स्वान के अन्तर्गत कनेक्टेड राजकीय विभागों/कार्यालयों/इकाईयों के ई–शासन कार्य प्रणाली तथा कार्य सम्पादन में वृद्धि।	एक वर्ष
		योग	**3990.00**	**0.01**					

सतत् विकास लक्ष्यों हेतु प्रारूप

क्र. सं.	एस.डी.जी. संकेतक	01.04.2023 को भौतिक स्थिति	31.03.2024 की संभावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित आउटपुट (भौतिक स्थिति) 2024–25	परिकल्पित आउटकम (भौतिक स्थिति) 2024–25	टिप्पणी
1	9c.2. Percentage of Gram Panchayats Covered under Bharat Net भारत नेट में शामिल ग्राम पंचायतो का प्रतिशत।	19.43%	25%	-	Rural Communities of the State would gain better access to reliable internet and telecommunications services and they can reap economic growth such as improved connectivity enables rural businesses to participate in the digital economy, opening doors to broader markets and increased revenues.	Data for GPs covered under Bharat Net taken from BBNL site. Additionally, MoU between ITDA and BSNL has been initiated for FTTH Connectivity for 1221 GPs out of which 865 GPs has been covered and rest will be completed upto March 2024.
2	**16.6.1. Number** of government services provided online to citizens नागरिकों को ऑनलाइन प्रदत्त की गई सरकारी सेवाओं की संख्या।	569	800	1000	• Efficiency • Timely delivery (75%) • Processing rate (99%) • Reduce pending rate (1%) • Accountability of officer for services delivery (Right service commission) • Transparency	
3	16.9.3. Proportion of population covered under Aadhaar (in percentage) आधार के अन्तर्गत शामिल जनसंख्या का अनुपात	100%	100%	100%	Better implementation of various State Government schemes related to Social Development and Direct Benefit Transfer (DBT).	Presently 105.50% Aadhar generated against Projected Population 1,16,37000.00 (as per census 2011) and Actual Aadhar Generated 1,22,77140.00
4	16.6.1. Percentage of functional Common Service Centre (CSC). कुल कियाशील कॉमन सर्विस सैण्टरों का प्रतिशत।	57.43%	61%	70%	• Benefit to the Rural public • All kind of government services and other services under 1 roof @Door Step nearest place • timely delivery and efficiency • Transparency • Reduce pending	March 2023 - registered 22464 Active 12902 31 Dec 2023 Registered 24361 Active 12513 15000